

Daily Current Affairs

Date : 10 September, 2025



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	महाराणा प्रताप एवं ट्राइबल ट्रिस्ट सर्किट
2.	राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025
3.	खण्डेला में यूरेनियम खनन
4.	IPS संपत मीना
5.	समाज कल्याण सप्ताह, 2025 : 1 से 7 अक्टूबर
6.	माँ वाउचर योजना
7.	नागालैंड से प्राप्त जीवाश्म
8.	भारत का हरित विकास मॉडल
9.	स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार और आर्द्रभूमि शहर मान्यता समारोह 2025
10.	आईईपीएफए का 9वां स्थापना दिवस
11.	यूपीआई-यूपीयू एकीकरण
12.	भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव 2025
13.	संयुक्त सैन्य अभ्यास 'जापाद 2025'
14.	40वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा

--:1:--



राजस्थान परिदृश्य



महाराणा प्रताप एवं ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट



चर्चा में क्यों?

- 9 सितम्बर, 2025 को मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गौरवशाली इतिहास तथा जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए कृतसंकल्पित, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट एवं ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित किया।



मुख्य बिन्दु:

	महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट	ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट
स्थल	इस सर्किट में महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों जैसे चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर आदि को सम्मिलित किया गया।	सीतामाता अभयारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृ कुण्डिया सहित विभिन्न पर्यटक स्थलों को शामिल किया गया।
आवंटित राशि	100 करोड़ रुपये	100 करोड़ रुपये।
विकास/निर्माण	<ol style="list-style-type: none">चेतक का स्मारक : हल्दीघाटी।हल्दीघाटी युद्ध : हल्दीघाटी के युद्ध का जीवंत चित्रण पर्यटकों को दिखाने के लिए थ्रीडी तकनीक, लाइट एण्ड साउण्ड शो जैसी आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा।चावंड का विकास : महाराणा प्रताप के समाधि स्थल चावंड का विकास किया जाएगा।विजय स्तंभ : दिवेर विजय के प्रतीक के रूप में विजय स्तंभ का निर्माण किया जाएगा।स्मृति चिह्न तथा स्मारक : दिवेर, गोगुंदा तथा चित्तौड़गढ़ में प्रताप के जीवन से जुड़े स्थानों पर विभिन्न स्मृति चिह्न तथा स्मारक आदि विकसित किए जायेंगे।	<ol style="list-style-type: none">मानगढ़ धाम का विकासबेणेश्वर धाम का विकास : यहां स्थित घाटों को नया स्वरूप देकर सुविधाएं विकसित की जाएगी।डूंगर बरंडा का स्मारक : डूंगरपुरबांसिया चारपोटा का स्मारक : बांसवाड़ा

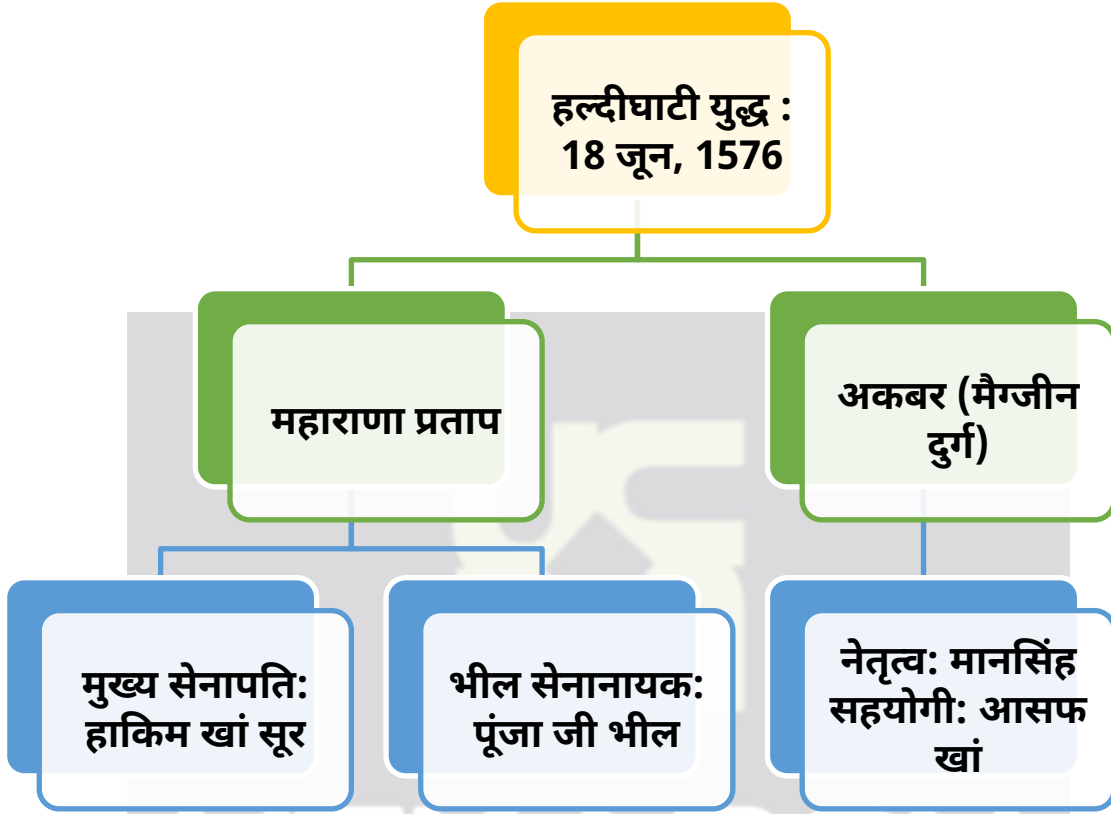
अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु :

महाराणा प्रताप :

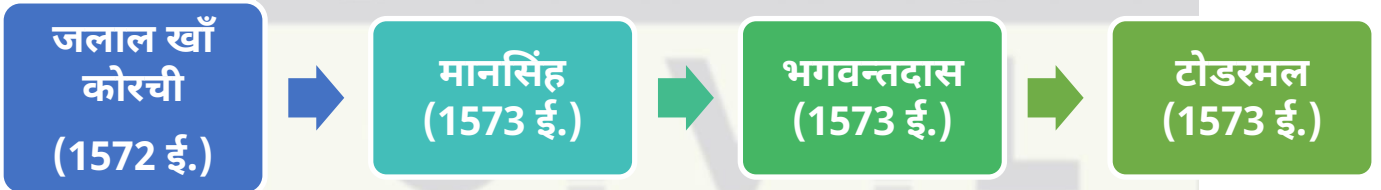
- महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा : कनेरा, चित्तौड़।
- पहली बार विदेश में 'महाराणा प्रताप महोत्सव' का आयोजन किया गया : जॉर्जिया
- पहली बार विदेश में महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित की गई : मॉरीशस

जीवन परिचय

- जन्म : 9 मई, 1540 (ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया) को बादल महल (कटारगढ़) कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था।
- शासनकाल : 1572-1597 ई.
- उपनाम : 'कीका' (मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों में), मेवाड़ केसरी, हिन्दुआ सूरज।
- राज्याभिषेक : 28 फरवरी, 1572 को महादेव बावड़ी (गोगुन्दा) तथा विधिवत् राज्याभिषेक; कुंभलगढ़ दुर्ग।
- प्रताप के हाथी : रामप्रसाद व लूणा।
- प्रमुख युद्ध : हल्दीघाटी का युद्ध (राजसमन्द) : 18 जून, 1576 और दिवेर का युद्ध (अक्टूबर, 1582)।



- अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने हेतु चार शिष्टमण्डल भेजे-



सांस्कृतिक उपलब्धियाँ :

- मंदिर : चामुण्डा देवी (चावण्ड), हरिहर मंदिर (बदराणा), नीलकण्ठेश्वर महादेव मंदिर और झालरा तालाब (मालपुरा टोंक)।
- दरबारी विद्वान :
 - पंडित चक्रपाणि मिश्र : विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहारदर्श व राज्याभिषेक पद्धति।
 - जैन मुनि हेमरत्न सूरी : गोरा-बादल, पद्मिनी चरित्र चौपाई, महिपाल चौपाई, अमरकुमार चौपाई, सीता चौपाई, लीलावती

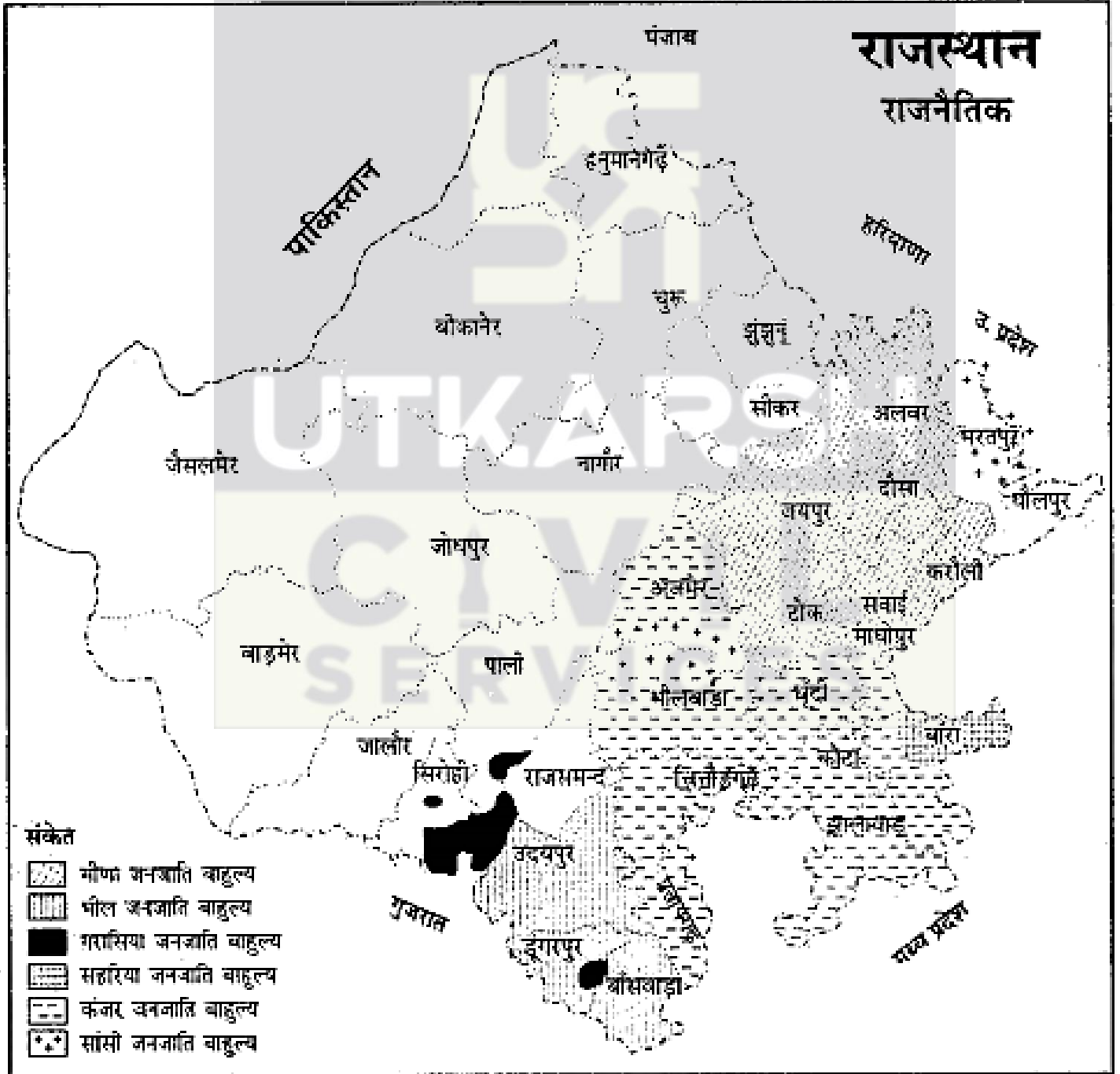
Daily Current Affairs

Date : 10 September, 2025



- **महाराणा प्रताप एवं गुरु वशिष्ठ पुरस्कार** : यह पुरस्कार राज्य के सर्वोत्तम खेल पुरस्कार हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को दिए जाते हैं। (पुरस्कार की राशि 5-5 लाख रुपये)।

राजस्थान में जनजातियाँ :



--:5:--

राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025

चर्चा में क्यों?

- 9 सितम्बर, 2025 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 ध्वनिमत से पारित किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- उद्देश्य : किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा धोखाधड़ी, बलपूर्वक या अनुचित प्रभाव के माध्यम से किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने पर अंकुश लगाना।

प्रावधान :

- जिन संपत्तियों का उपयोग जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के लिए किया गया है, उनकी जब्ती की जा सकेगी।
- विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन करवाने के उद्देश्य से किया गया विवाह, फैमिली कोर्ट या इस विधेयक में निर्धारित अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
- नए विधेयक के अंतर्गत धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा अधिकृत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वेच्छा से एवं बिना किसी दबाव के धर्म परिवर्तन करने की जानकारी 90 दिन पूर्व देनी होगी। ऐसा नहीं करने की स्थिति में न्यूनतम 7 से 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

Daily Current Affairs

Date : 10 September, 2025



4. धर्म परिवर्तन करवाने वाले धर्माचार्य को जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष धर्म परिवर्तन का नोटिस 2 माह पूर्व देना होगा। उल्लंघन की स्थिति में न्यूनतम 10 से 14 वर्ष तक की सजा और न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
5. **कारावास और अर्थदंड :**

अपराध	कारावास	अर्थदंड
छल कपट से धर्म परिवर्तन करने पर	7 से 14 वर्ष तक का कारावास	न्यूनतम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना
अल्प वयस्क, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन आदि को कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन करवाने पर	न्यूनतम 10 से 20 वर्ष तक का कारावास	न्यूनतम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना
कपटपूर्ण तरीकों से सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने वाले व्यक्ति को	न्यूनतम 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा	न्यूनतम 25 लाख रुपए का जुर्माना
धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी एवं अवैध संस्थाओं से धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को	न्यूनतम 10 से 20 वर्ष तक का कठोर कारावास	न्यूनतम 20 लाख रुपए का जुर्माना
धर्म परिवर्तन करवाने के लिए किसी व्यक्ति को जीवन, संपत्ति के लिए धमकाने वाले, झांसा देकर विवाह करने, बेचकर दुर्व्यापार करने या इस निमित्त दुष्प्रेरित करने वाले व्यक्ति को	न्यूनतम 20 वर्ष लेकर आजीवन कारावास तक की सजा	न्यूनतम 30 लाख रुपए तक का जुर्माना
धर्म परिवर्तन के लिए पूर्व में दोषी सिद्ध अपराधी को पुनः दोष सिद्ध होने पर	न्यूनतम 20 वर्ष लेकर आजीवन कारावास तक की सजा	न्यूनतम 50 लाख रुपए तक का जुर्माना

--7--

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु :

विभिन्न राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानून :

राज्य	वर्ष
अरुणाचल प्रदेश	1978
आंध्र प्रदेश	2007
उत्तराखंड	2018
हिमाचल प्रदेश	2019
उत्तर प्रदेश	2021
कर्नाटक	2021
हरियाणा	2022

- भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित प्रावधान : भाग III (मौलिक अधिकार) , भाग IV (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत) और भाग IV (मौलिक कर्तव्य) में निहित।

प्रावधान	विवरण
प्रस्तावना	42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 'धर्मनिरपेक्ष' का अर्थ: एक ऐसा गणराज्य जिसमें सभी धर्मों के लिए समान सम्मान हो।
अनुच्छेद 14	विधि के समक्ष समता (कानून के सामने समानता) या विधियों का समान संरक्षण
अनुच्छेद 16 (1)	सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों को अवसर की समानता और धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान और निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

Daily Current Affairs

Date : 10 September, 2025



अनुच्छेद 25	यह 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता' प्रदान करता है, अर्थात सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है।
अनुच्छेद 26	प्रत्येक धार्मिक समूह या व्यक्ति को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव करने तथा धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है।
अनुच्छेद 27	राज्य किसी भी नागरिक को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
अनुच्छेद 28	यह विभिन्न धार्मिक समूहों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है।
अनुच्छेद 29 और 30	अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ।
अनुच्छेद 51A	यह सभी नागरिकों को सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने तथा हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने के लिए बाध्य करता है।

--9:--

खण्डेला में यूरेनियम खनन

चर्चा में क्यों?

- सीकर जिले की तहसील खण्डेला में यूरेनियम खनन से सम्बंधित परियोजना के तहत कार्यकारी संस्था यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (UCIL) की ओर से लगभग 3 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा।



--:10:--



मुख्य बिन्दु:

- **प्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन** : 1623 नागरिकों को, जिसमें लगभग 80 प्रतिशत स्थानीय लोग शामिल होंगे।

यूरेनियम की विस्तृत खोज (Exploratory Mining) का कार्य :

- यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (UCIL)
- परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (AMD)
- परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE)
- राज्य सरकार द्वारा सीकर जिले की तहसील खण्डेला में UCILके पक्ष में खनिज यूरेनियम एवं एसोसिएटेड मिनरल्स 1086.46 हैक्टेयर क्षेत्र के खनन पट्टा आवंटन हेतु मंशा पत्र (Letter of Intent) 23 जून, 2022 को जारी किया गया है।
- मंशा पत्र क्षेत्र में निजी भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत प्रक्रियाधीन है।
- **Note:** सीकर जिले की खण्डेला तहसील के रोहिल में 1086.46 हैक्टेयर क्षेत्र में यूरेनियम के विपुल भण्डार खोजे गए।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :

- **यूरेनियम** : परमाणु उर्जा के लिए यूरेनियम बहुमूल्य दुर्लभ खनिज है।
- **उपयोग** : विद्युत, दवा, रक्षा उपकरणों, फोटोग्राफी सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है।
- **विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन** : कजाकिस्तान, कनाडा और आस्ट्रेलिया।
- **भारत में यूरेनियम की भंडार** : झारखण्ड के सिंहभूम और राजस्थान की धारवाड़ एवं आर्कियन चट्टानों, उत्तरी बिहार, आन्ध्र प्रदेश के नैल्लौर, राजस्थान के अभ्रक के क्षेत्रों में पैग्मेटाइट चट्टानों में, केरल के समुद्र तटीय भागों में मोनोजाइट निक्षेपों में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लु, चमोली जिलों की चट्टानों में यूरेनियम प्राप्त किया जाता है।

राजस्थान में आणविक ऊर्जा खनिज उत्पादक क्षेत्र :

क्र. सं.	खनिज	स्थान
1	यूरेनियम	उमरा, उदयपुर (सर्वाधिक), खण्डेला, रोहिल क्षेत्र (सीकर), भणास, जहाजपुरा (भीलवाड़ा)
2	थोरियम	भद्रावन (पाली), सरदारपुरा (भीलवाड़ा)।
3	बेरिलियम	चंपागुड़ा, शिकारबाड़ी (उदयपुर), मकरेड़ा (भीलवाड़ा), आमेट (राजसमंद)

--:11:--

राजस्थान में खनिज संसाधन :

खनिज भण्डारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान	दूसरा (पहला : झारखण्ड)।
खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश में स्थान	तीसरा (पहला: मध्यप्रदेश, दूसरा : छत्तीसगढ़)।
राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्धता वाला खनिज	रॉक फॉस्फेट
राजस्थान ; एकमात्र उत्पादक राज्य	सीसा एवं जस्ता अयस्क, सेलेनाइट और वॉलेस्टोनाइट
राजस्थान ; लगभग पूरा उत्पादन	चाँदी, केलसाइट और जिप्सम
राजस्थान ; प्रमुख उत्पादक	बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, ओकर, स्टिएटाइट, फेल्सफार एवं फायर क्ले
राजस्थान ; अग्रणी उत्पादक	सीमेन्ट ग्रेड व स्टील ग्रेड और लाइम स्टोन
राजस्थान ; लगभग एकाधिकार प्राप्त	संगमरमर, सीसा, जस्ता, चाँदी, बोलस्टोनाइट, जास्पर, फलोराइट, जिप्सम, ऐस्बेस्टॉस, रॉकफॉस्फेट, टंगस्टन, तथा तामड़ा।

राजस्थान में खनिजों का वर्गीकरण :

राजस्थान में खनिजों का वर्गीकरण



--:12:--

IPS संपत मीना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, झारखंड कैडर 1994 बैच की CBI संपत मीणा को एडिशनल डायरेक्टर से पदोन्नत कर स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किया गया।



मुख्य बिन्दु:

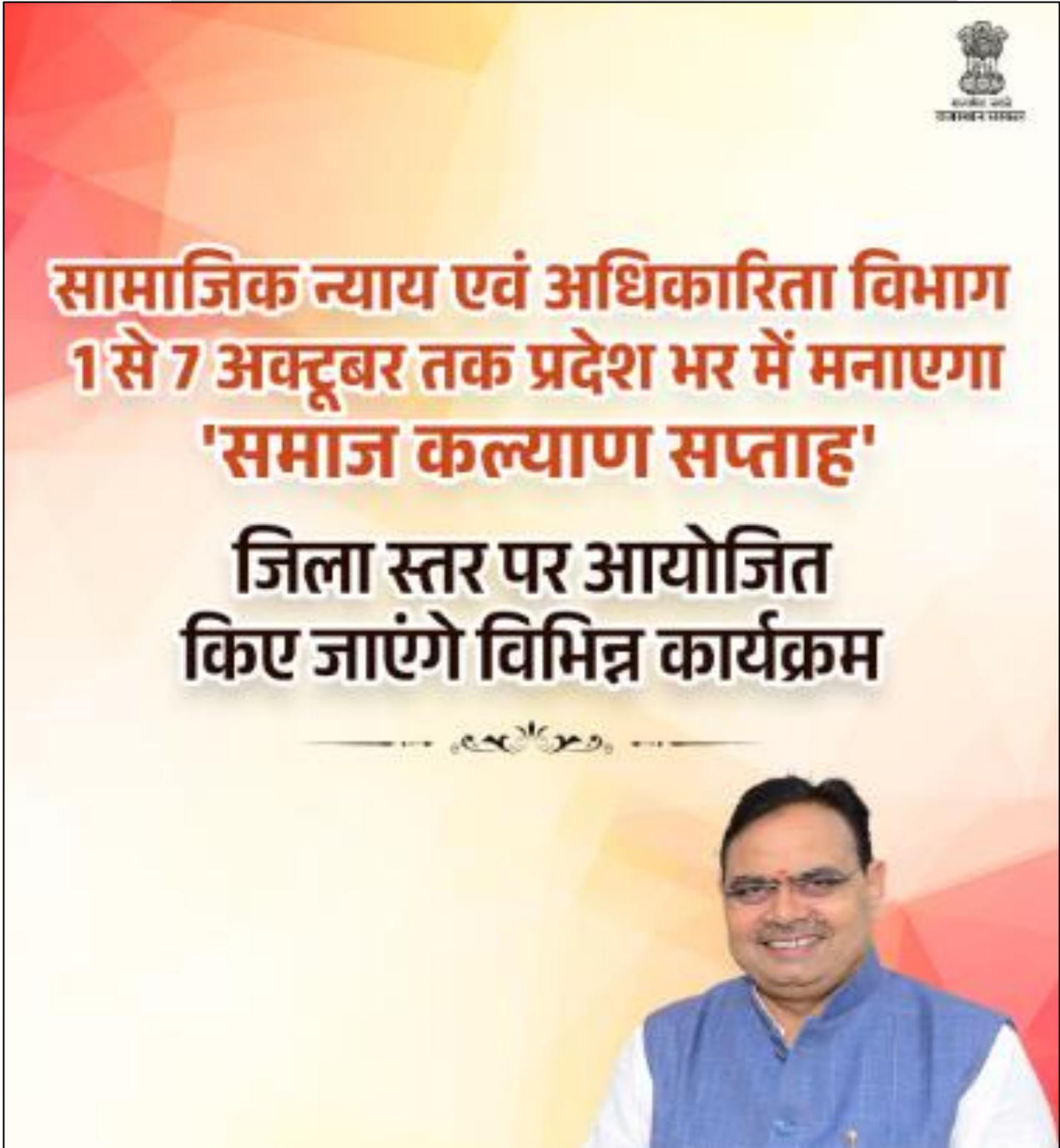
- मूल निवासी : पुरा जोलंदा गांव, सवाई माधोपुर।
- इससे पूर्व CBI में अतिरिक्त निदेशक के पद पर थीं।
- संपत मीणा ने हाथरस-उन्नाव केस के बाद कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर बहु चर्चित मामले की सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
- संपत को तीन बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जा चुका है।

समाज कल्याण सप्ताह, 2025 : 1 से 7 अक्टूबर



चर्चा में क्यों?

- प्रतिवर्ष 1 से 7 अक्टूबर, 2025 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश भर में समाज कल्याण सप्ताह मनाएगा।



Daily Current Affairs

Date : 10 September, 2025



मुख्य बिन्दु:

- मुख्य उद्देश्य : अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विशेष योग्यजन, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने के साथ-साथ सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों के विरुद्ध जनचेतना जागृत करना।

सप्ताह के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों को दिवसों में बाँटा गया है-

तिथि	आयोजन
1 अक्टूबर	अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस
2 अक्टूबर	अनुसूचित जातियों का कल्याण दिवस
3 अक्टूबर	अपराधी सुधार दिवस
4 अक्टूबर	बाल दिवस
5 अक्टूबर	महिला एवं बालिका कल्याण दिवस
6 अक्टूबर	जन चेतना दिवस
7 अक्टूबर	विशेष योग्यजन कल्याण दिवस

--:16:--

माँ वाउचर योजना

चर्चा में क्यों?

- 9 सितंबर, 2025 को विधानसभा सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में प्रदेश में संचालित माँ वाउचर योजना के संबंध में जानकारी साझा की।



मुख्य बिन्दु:

- प्रदेश में संचालित माँ वाउचर योजना के तहत दूसरी एवं तीसरी तिमाही की गर्भवती माताओं को राजकीय सोनोग्राफी जाँच उपलब्ध नहीं होने पर वाउचर जारी किया जाता है।
- क्यूआर कोड जनित वाउचर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को निजी सोनोग्राफी केन्द्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा दी जाती है।
- इस योजना के तहत प्रदेश के 1 हजार 363 निजी सोनोग्राफी केन्द्रों को अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इन निजी केंद्रों को सीधे बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।
- माँ वाउचर योजना के तहत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाने का प्रावधान नहीं है।

Daily Current Affairs

Date : 10 September, 2025



विधानसभा क्षेत्र सोजत :

- विधानसभा क्षेत्र सोजत पाली में माँ वाउचर योजना के तहत 17 सितम्बर, 2024 से 04 सितम्बर, 2025 तक 5 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केन्द्रों पर 583 सोनोग्राफी की गई है।
- विधानसभा क्षेत्र सोजत में संचालित चिकित्सालयों में केवल जिला चिकित्सालय सोजत में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध है व क्रियाशील है, सीटी स्कैन मशीन पीपीपी मोड पर संचालित है।
- अन्य राजकीय संस्थानों जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इन मशीनों का प्रावधान नहीं है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :

माँ वाउचर योजना :

- **घोषणा :** बजट 2024-25
- **शुभारंभ :** 17 सितम्बर, 2024 को सम्पूर्ण प्रदेश।
- **उद्देश्य :** प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी सुविधा में विस्तार करना।
- **नोडल विभाग :** चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार।
- **लाभ :** योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दूसरी व तीसरी तिमाही में निःशुल्क सोनोग्राफी के लिए वाउचर दिए जाते हैं जिनकी जारी दिनांक के 30 दिवस तक रहती है।
- जिनकी वैद्यता किसी कारणवश इस अवधि में वाउचर का उपयोग नहीं कर पाने की स्थिति में महिला द्वारा चिकित्सा संस्थान जाकर वैद्यता अवधि को आगामी 30 दिन तक बढ़वाया जा सकता है।

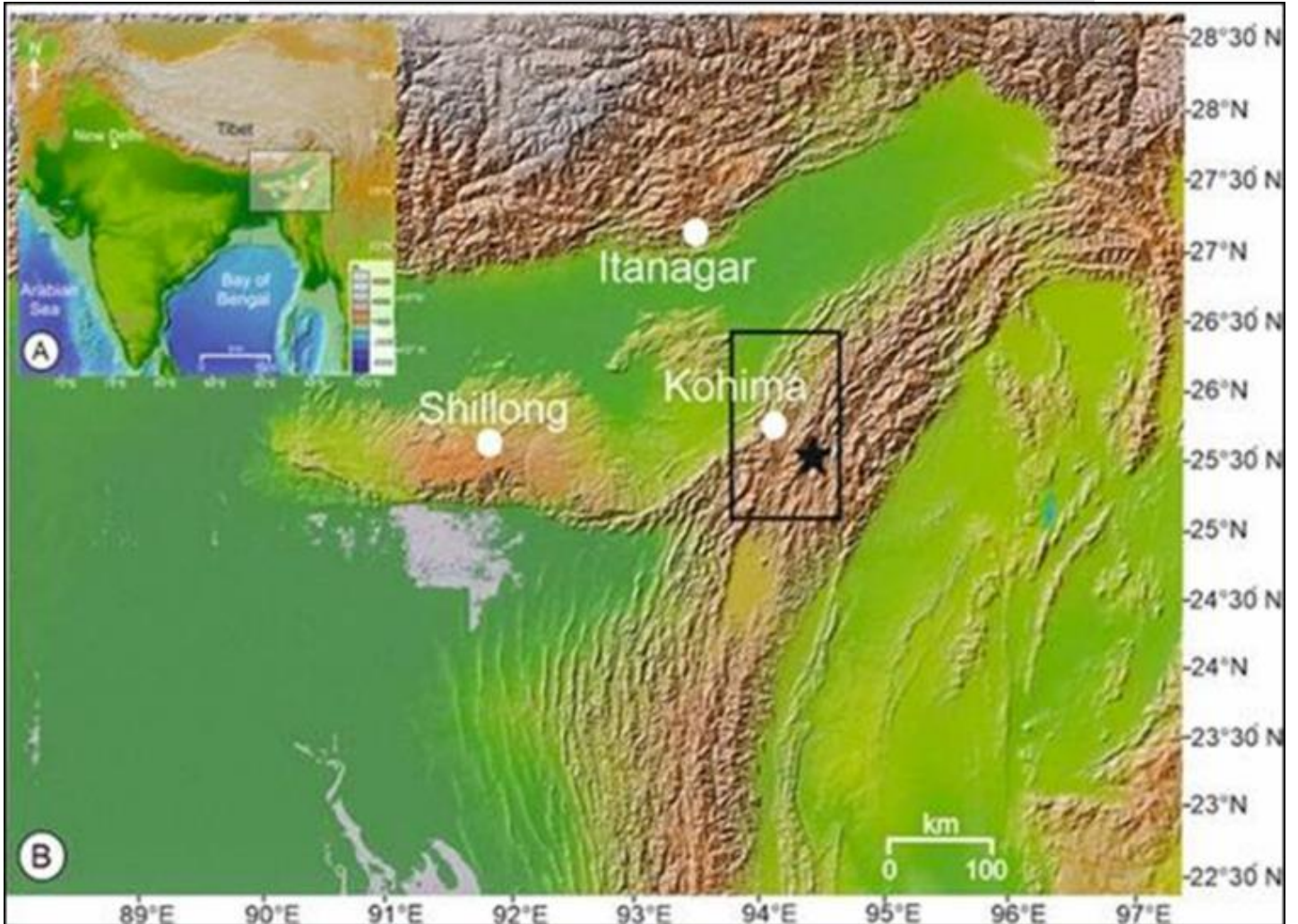
--:18:--

राष्ट्रीय परिदृश्य

नागालैंड से प्राप्त जीवाश्म

चर्चा में क्यों?

- हाल के अध्ययन ने लगभग 34 मिलियन वर्ष पहले अंटार्कटिका के निर्माण और भारतीय मानसून प्रणाली के प्रारंभिक विकास के बीच संबंध स्थापित किया।
- यह अध्ययन नागालैंड में लाइसोंग संरचना से प्राप्त 34 मिलियन वर्ष पुरानी संरक्षित जीवाश्म पत्तियों पर आधारित है, जिनसे पता चला है कि इस क्षेत्र में कभी गर्म और आर्द्र जलवायु रही थी।





मुख्य बिन्दु:

शोध और निष्कर्ष:

- जीवाश्म पत्तों का अध्ययन करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के स्वायत्त संस्थानों, बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान (लखनऊ) और वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान (देहरादून) के वैज्ञानिकों ने जलवायु पुनर्निर्माण किया।
- उन्होंने पाया कि इस समय अंटार्कटिका में विशाल बर्फ की चादरें बनना शुरू हुई थीं, जो वैश्विक वायु और वर्षा पैटर्न में बदलाव का कारण बनीं। इससे पूर्वोत्तर भारत में तीव्र मानसूनी बारिश हुई और भारतीय मानसून प्रणाली का विकास हुआ।

आधुनिक जलवायु परिवर्तन का संकेत:

- आईटीसीजेड (Intertropical Convergence Zone) का स्थान परिवर्तन, जो प्रमुख वर्षा पट्टी है, दक्षिणी ध्रुव से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर खिसक गया, जिससे भारत में असाधारण रूप से अधिक वर्षा और गर्म तापमान का अनुभव हुआ।
- यह अध्ययन यह बताता है कि अंटार्कटिका की बर्फ के जमाव का भारतीय मानसून पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे भारत की जलवायु और वर्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव हुए।

जलवायु परिवर्तन के वर्तमान प्रभाव:

- यह अध्ययन आज के जलवायु परिवर्तन से जुड़े एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में सामने आता है। अंटार्कटिका की बर्फ के पिघलने से आईटीसीजेड फिर से खिसक सकता है, जिससे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा पैटर्न प्रभावित हो सकते हैं।

भविष्य के लिए महत्व:

- यह अध्ययन यह बताता है कि पृथ्वी की जलवायु एक वैश्विक नेटवर्क की तरह काम करती है। पृथ्वी के एक हिस्से में होने वाला परिवर्तन पूरी दुनिया पर असर डालता है, चाहे वह अंटार्कटिका का बर्फीला क्षेत्र हो या नागालैंड के नम जंगल।
- इस अध्ययन से यह सीखने को मिलता है कि हमारे ग्रह ने लाखों साल पहले कैसे बदलावों पर प्रतिक्रिया दी, और इससे हमें भविष्य में बढ़ते तापमान के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिल सकती है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

भारत का हरित विकास मॉडल

चर्चा में क्यों?

- भारत ने 2025 में हरित विकास मॉडल को लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो पर्यावरणीय स्थिरता, स्वच्छ ऊर्जा और आर्थिक समावेशन की दिशा में देश के प्रयासों को उजागर करता है। इस मॉडल का लक्ष्य शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के साथ-साथ विकास और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संतुलन बनाए रखना है।



मुख्य बिन्दु:

प्रवृत्ति (Trend)	मुख्य पहल / प्रमुख खिलाड़ी
नवीकरणीय ऊर्जा	राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सोलर रूफटॉप पहल, अदाणी, टाटा पावर, रिन्यू पावर
ईएसजी निवेश	सेबी बीआरएसआर कोर, ईएसजी म्यूचुअल फंड्स, संप्रभु ग्रीन बॉन्ड, ईएसजी-आधारित कार्यकारी वेतन
परिपत्र अर्थव्यवस्था	प्लास्टिक प्रतिबंध, ईपीआर नियम, रिसायकल, अटैरो, वाहन स्क्रेप नीति, जहाज-तोड़ प्रोत्साहन
जलवायु तकनीक	ईवी बूम, ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ, हाइजेको (ग्रीन हाइड्रोजन), जीपीएस रिन्यूएबल्स, एक्सपोनेंट एनर्जी
जैव विविधता	प्रोजेक्ट टाइगर, चीता पुनःप्रवर्तन, आईबीसीए, मिश्टी, अमृत धरोहर, सामुदायिक इको-जॉब्स
जल प्रबंधन	जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, अटल भूजल योजना, जल-पॉजिटिव कंपनियाँ, वर्षा जल संचयन कानून
नियामक ढांचा	कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, बैटरी और ई-वेस्ट नियम, आरबीआई-सेबी जलवायु निगरानी

Daily Current Affairs

Date : 10 September, 2025



मुख्य स्तंभ:

ऊर्जा संक्रमण:

- **नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य:** भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है।
- **रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि:** 2025 में भारत ने 43 गीगावाट नई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी। कुल स्थापित क्षमता 223.6 गीगावाट तक पहुँच चुकी है।
- **सौर ऊर्जा वृद्धि:** सौर ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट को पार कर गई है, जो नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख योगदानकर्ता है।
- **जैव ईंधन:** पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण और बायोमास सह-फायरिंग बढ़ाई जा रही है।

हरित हाइड्रोजन मिशन:

- **वैश्विक केंद्र बनने की दिशा:** भारत हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने का लक्ष्य रखता है।
- **उत्पादन प्रोत्साहन:** ₹17,000 करोड़ के बजट के साथ इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सर्कुलर अर्थव्यवस्था:

- **नए नियम:** ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- **अपशिष्ट प्रबंधन:** गोबरधन योजना के तहत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति और वाहन स्क्रैपिंग नीति से अपशिष्ट को कम करने की कोशिश की जा रही है।

सतत गतिशीलता:

- **इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी):** उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **सार्वजनिक परिवहन विद्युतीकरण:** भारतीय रेलवे अपने मिशन "100% विद्युतीकरण" के तहत 2030 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है।

सतत वित्त और निवेश:

- **बजटीय सहायता:**
- **ग्रीन बॉन्ड:** ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ग्रीन बॉन्ड का उपयोग बढ़ाया जा रहा है।

--:22:--

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार और आर्द्रभूमि शहर मान्यता समारोह 2025

चर्चा में क्यों?

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 8 सितंबर 2025 को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार और आर्द्रभूमि शहर मान्यता समारोह आयोजित किया।



मुख्य बिन्दु:

- आईईपीएफए द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के तहत 130 शहरों में से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के प्रमुख शहर और पुरस्कार:

- श्रेणी-1 (10 लाख से अधिक जनसंख्या):**
 - इंदौर ने 200 में से 200 अंक प्राप्त कर पहला स्थान प्राप्त किया।
 - जबलपुर: दूसरा स्थान
 - आगरा और सूरत: तीसरा स्थान
- श्रेणी-2 (3 से 10 लाख की जनसंख्या):**
 - अमरावती: पहला स्थान
 - झांसी और मुरादाबाद: दूसरा स्थान
 - अलवर: तीसरा स्थान

आर्द्रभूमि शहर मान्यता योजना:

- इंदौर और उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता मिली।
- निवेश और वित्तीय समर्थन:**
 - केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और फेम-II से इन योजनाओं का वित्तपोषण किया जा रहा है।
 - "प्राण" पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफार्म से शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित की गई।

आर्थिक परिदृश्य

आईईपीएफ का 9वां स्थापना दिवस

चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) ने 08 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में 9वां स्थापना दिवस मनाया।



मुख्य बिन्दु:

- इस वर्ष का सम्मेलन "अदावाकृत का दावा: भारत में निष्क्रिय वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षमता को उजागर करना" विषय पर आयोजित किया गया।

वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता:

- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और निवेशकों के विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए साझा प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर जोर दिया।
- उन्होंने प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और विश्वास के आधार पर सुधारों के माध्यम से निवेशक हितों की सुरक्षा की दिशा में आईईपीएफ की यात्रा पर जोर दिया गया।

आईईपीएफ:

- निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) की स्थापना 7 सितंबर, 2016 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन की गई थी और इसका उद्देश्य निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि का प्रबंधन करना है।
- यह निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और देश भर में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

Daily Current Affairs

Date : 10 September, 2025

UTKARSH
CLASSES

CIVIL
SERVICES

यूपीआई-यूपीयू एकीकरण



UNIVERSAL
POSTAL
UNION



UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

UNION MINISTER FOR COMMUNICATIONS AND
DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA

TO LAUNCH

UPI-UPU PROJECT



DUBAI WORLD
TRADE CENTRE



8TH SEPTEMBER,
2025



7:00 PM
(GST)



--:25:--



मुख्य बिन्दु:

यूपीआई-यूपीयू एकीकरण की शुरुआत:

- केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुबई में 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई-यूपीयू एकीकरण का शुभारंभ किया।
- इस परियोजना का विकास डाक विभाग (डीओपी), एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) द्वारा किया गया है।

यूपीआई और यूपीयू का समन्वय:

- यह पहल भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को यूपीयू इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म (आईपी) से जोड़ती है, जिससे डाक नेटवर्क की पहुंच को यूपीआई की गति और सामर्थ्य के साथ जोड़ा जाता है।
- इससे सीमा पार प्रेषण को किफायती तरीके से किया जा सकेगा, जो न केवल तेजी से, बल्कि सुरक्षित भी होगा।

राजव्यवस्था

भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव 2025

चर्चा में क्यों?

- नए उपराष्ट्रपति: सीपी राधाकृष्णन 9 सितंबर, 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए।

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025



सीपी राधाकृष्णन
452 वोट



जीत का
अंतर- 152 वोट



बी. सुदर्शन रेड्डी
300 वोट

मुख्य बिन्दु:

- चुनाव संदर्भ: यह चुनाव पिछले उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद हुआ।
- उम्मीदवार: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने सीपी राधाकृष्णन को नामित किया, जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को नामित किया।

--:27:--

- **परिणाम:** राधाकृष्णन 452 मतों के साथ विजयी हुए, जबकि रेड्डी को 300 मत मिले।
संवैधानिक प्रावधान
- **अनुच्छेद 63:** भारत के उपराष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है।
- **अनुच्छेद 64:** उपराष्ट्रपति को राज्य सभा (राज्य परिषद) का पदेन सभापति घोषित करता है।
- **अनुच्छेद 65:** रिक्ति की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या उसके कार्यों का निर्वहन करने में उपराष्ट्रपति की भूमिका को रेखांकित करता है।
- **अनुच्छेद 66:** उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है।
पात्रता मानदंड (अनुच्छेद 66)
- भारत का नागरिक।
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
- राज्य सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए।
- संघ, राज्य या किसी स्थानीय या सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करना।
चुनाव प्रक्रिया (अनुच्छेद 66)
- **निर्वाचक मंडल:** उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, शामिल होते हैं। राज्य विधान सभाएँ इसमें भाग नहीं लेतीं।
- उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र के लिए कम से कम 20 प्रस्तावकों और 20 समर्थकों द्वारा समर्थित होना आवश्यक है।
- **आनुपातिक प्रतिनिधित्व:** चुनाव में एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

Daily Current Affairs

Date : 10 September, 2025



- **गुप्त मतदान:** मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है।
- **आचरण:** भारत का चुनाव आयोग चुनाव की देखरेख करता है और एक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति करता है।

शक्तियाँ और कार्य

- **राज्य सभा के सभापति:** पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति राज्य सभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं।
- **कार्यवाहक राष्ट्रपति:** यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युति या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। वे अधिकतम छह महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिसके दौरान एक नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है।
- **परिलब्धियाँ:** राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।

-:29:-

सैन्य अभ्यास

संयुक्त सैन्य अभ्यास 'जापाद 2025'

चर्चा में क्यों?

- रूस और बेलारूस के नेतृत्व में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास 10-16 सितंबर, 2025 के लिए निर्धारित इस अभ्यास में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी सहित कई देश भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास रूस के मुलिनो प्रशिक्षण मैदान और बेलारूस के विभिन्न स्थलों सहित कई प्रशिक्षण मैदानों पर आयोजित किया जा रहा है।



मुख्य बिन्दु:

उद्देश्य

- **सैन्य सहयोग बढ़ाना:** यह अभ्यास भाग लेने वाले देशों, विशेष रूप से रूस और बेलारूस के बीच समन्वय में सुधार और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए बनाया गया है।

--:30:--

Daily Current Affairs

Date : 10 September, 2025



- **अंतर-संचालनीयता में सुधार:** यह विभिन्न सैन्य बलों को एक साथ काम करने तथा पारंपरिक युद्ध और आतंकवाद-रोधी अभियानों के लिए रणनीति और प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

प्रमुख प्रतिभागियों

- **मेजबान राष्ट्र:** रूस और बेलारूस ।
- **पूर्ण प्रतिभागी:** बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कांगो, माली, भारत, ईरान, नाइजर और ताजिकिस्तान ।
- **पर्यवेक्षक राष्ट्र:** कंबोडिया, चीन, क्यूबा, कजाकिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, निकारागुआ, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सर्बिया, थाईलैंड, यूएई और उज्बेकिस्तान ।
- **भारत का योगदान:** भारतीय सशस्त्र बलों की 65 कार्मिकों की एक टुकड़ी इसमें भाग ले रही है, जिसमें 57 थलसेना (कुमाऊं रेजिमेंट के नेतृत्व में), 7 वायुसेना और 1 नौसेना से हैं।

--:31:--

महत्त्वपूर्ण दिवस

40वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा

चर्चा में क्यों?

- 40वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर, 2025 तक आयोजित किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला यह राष्ट्रव्यापी अभियान नेत्रदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और कॉर्नियल अंधेपन से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए अपनी आंखें दान करने का संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

2025 पखवाड़े के बारे में मुख्य तथ्य:

- विषय :** 40वीं वर्षगांठ का विषय था "रोज़मर्रा के नायक"।

अभियान के लक्ष्य

- अभियान का उद्देश्य कॉर्नियल प्रत्यारोपण की संख्या में वृद्धि करना, दृष्टि बहाल करना तथा कॉर्नियल अंधेपन से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाना था।